# ई संदेश

08 जनवरी, 2026 | अंक -187

## सात दिन सात पृष्ठ

## नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से भेंट करते मुख्यमंत्री जी।

प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 72वीं 'सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप' का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारम्भ किया, इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्मिलित हुए

भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यह दुनिया की सबसे तेज गति से उभरने वाली अर्थव्यवस्था भी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने 'विकसित भारत-गारण्टी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' अधिनियम-2025 पारित करने के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया

सभी विभाग आवंटित बजट का समय से प्रयोग करें ताकि योजनाएं समय से पूर्ण हो सकें और प्रदेशवासियों को इसका लाभ मिले : मुख्यमंत्री

राजस्व के सभी मामलों का निपटारा मेरिट के आधार पर तय हो : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 06 जनवरी, 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

**नए भारत का नया उत्तर प्रदेश**

# प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 72वीं 'सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप' का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारम्भ किया, इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्मिलित हुए

## 72वीं 'सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप' में एकत्रित हुईं 28 राज्यों की टीमें 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का सुन्दर चित्र प्रस्तुत करतीं हैं : प्रधानमंत्री

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 04 जनवरी, 2026 को डॉ0 सम्पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिगरा, वाराणसी में आयोजित 72वीं 'सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप' का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सम्मिलित हुए।

प्रधानमंत्री जी ने आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली सम्बोधित करते हुए कहा कि उन्हें वाराणसी से सांसद होने के नाते सभी खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनन्दन करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। देश के 28 राज्यों की टीमें 72वें 'सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप' में एकत्रित हुईं हैं, जो 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का सुन्दर चित्र प्रस्तुत करती हैं। खिलाड़ी अथक परिश्रम के बाद इस राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट तक पहुंचे हैं।

प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वॉलीबॉल कोई साधारण खेल नहीं, बल्कि सन्तुलन और सहयोग का खेल है, जहां गेंद को हमेशा हवा में रखने के प्रयास में दृढ़ संकल्प की झलक दिखती है। वॉलीबॉल खिलाड़ियों को टीम भावना से जोड़ता है, जहां प्रत्येक खिलाड़ी 'टीम पहले' के मंत्र से प्रेरित होता है। भले ही प्रत्येक खिलाड़ी के पास अलग-अलग कौशल हों, लेकिन सभी अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं। उन्होंने कहा कि यह खेल हमें सिखाता है कि कोई भी जीत अकेले प्राप्त नहीं होती। सफलता तभी मिलती है, जब प्रत्येक खिलाड़ी गम्भीरता से अपनी जिम्मेदारी निभाता है।

प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के विकास और अर्थव्यवस्था की सराहना कर रही है। यह प्रगति केवल आर्थिक मोर्चे तक ही सीमित नहीं, बल्कि खेल जगत में दिख रहे आत्मविश्वास में भी झलकती है। हाल के वर्षों में, वर्ष 2014 से विभिन्न खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। मुझे जेन-जेड खिलाड़ियों को मैदान पर तिरंगा फहराते देखकर गर्व की अनुभूति होती है।सरकार ने खेल के क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए हैं, जिनमें राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम और खेलो भारत नीति-2025 शामिल हैं। इनसे प्रतिभाओं को अवसर मिलेंगे और खेल संगठनों में पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे युवाओं को खेल और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। 'टॉप्स' (टॉरगेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम) जैसी पहल भारत में खेल जगत को बदल रही हैं। इसमें मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने, वित्तपोषण तंत्र विकसित करने और युवा खिलाड़ियों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 'खेलो इण्डिया' अभियान के माध्यम से सैकड़ों युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। कुछ दिन पूर्व 'सांसद खेल महोत्सव' का समापन हुआ, जिसमें लगभग एक करोड़ युवाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 'सांसद खेल महोत्सव' के दौरान वाराणसी के लगभग तीन लाख युवाओं ने मैदान पर अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया। वाराणसी में आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित की जा रहीं हैं। सिगरा स्थित स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर प्रदान कर रहा है।

प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के माध्यम से वाराणसी का देश के खेल नक्शे पर स्थान बनाना शहर के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व, वाराणसी ने कई महत्वपूर्ण आयोजनों की मेजबानी की है, जिससे स्थानीय लोगों को पर्याप्त अवसर और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। ऐसे आयोजन वाराणसी को बड़े मंचों के लिए एक प्रमुख गन्तव्य के रूप में स्थापित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने चैम्पियनशिप के सभी प्रतिभागियों को टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा शुभकामनाएं दीं।

## खेल जीवन के सर्वांगीण विकास का माध्यम, विगत 11 वर्षों में प्रत्येक भारतवासी ने देश में नई खेल संस्कृति को पनपते हुए देखा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि विगत 11 वर्षों में प्रत्येक भारतवासी ने देश में नई खेल संस्कृति को पनपते हुए देखा है। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2014 में 'खेलो इण्डिया' के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी के मन में खेल के प्रति सम्मान का भाव पैदा किया है। खेल अब जीवन के सर्वांगीण विकास का माध्यम है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 'खेलो इण्डिया', 'फिट इण्डिया मूवमेन्ट', 'सांसद खेल-कूद प्रतियोगिता' तथा प्रत्येक जनपद में बनने वाले खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से पूरा देश नई खेल संस्कृति का अनुभव कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 'विधायक खेल-कूद' प्रतियोगिता और ग्रामीण खेल-कूद लीग एवं प्रतियोगिताओं के माध्यम से खेलों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज गाँव से शहर तक तथा ग्रामीण स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं आम नागरिकां के लिए आयोजित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 43 वर्षों के पश्चात यह 'सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप' उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर निगम द्वारा प्रायोजक के रूप में आयोजित की जा रही है। इस पूरे आयोजन के पीछे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है। आज देश केपुरुष और महिलाओं की कुल 58 टीमें, प्रधानमंत्री जी की कर्म साधना की पावन धरा अविनाशी काशी में पधारी हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के विजन और दृढ़ इच्छाशक्ति से आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के नए मॉडल का प्रत्येक भारतवासी लाभ प्राप्त कर रहा है। सम्पूर्ण देश ने विगत 11 वर्षों में भारत के समग्र विकास को अपनी आंखों से देखा है। बदलता हुआ नया भारत अपनी विरासत और आधुनिक विकास पर गौरव की अनुभूति कर रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में प्रदेश सहित देश में खेल का आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है। डॉ0 सम्पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम में विकसित अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रधानमंत्री जी के विज़न का परिणाम है। यह सभी सुविधाएं स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत यहां विकसित की गयी है। उत्तर प्रदेश सरकार और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) के बीच एक एम0ओ0यू0 भी यहां सम्पन्न हुआ है। इसके अंतर्गत अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। एस0ए0आई0 के सान्निध्य तथा प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण तथा नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत 08 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक गाँव में खेल का मैदान, प्रत्येक जनपद में स्टेडियम, प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम, ग्राम पंचायत और नगर निकाय स्तर पर ओपन जिम का निर्माण सहित खेल-कूद से जुड़ी अनेक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। परिणामस्वरूप ओलम्पिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जैसी प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में प्रदेश के खिलाड़ी देश की टीम में प्रतिभाग कर रहे है। वह देश के लिए पूर्व की तुलना में कई गुना अधिक मेडल भी प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों से मिलकर उनका मनोबल बढ़ाया तथा प्रतियोगिता हेतु शुभकामनाएं दीं।

# वाराणसी में 72वीं 'सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप' के शुभारम्भ की झलकियां

## भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यह दुनिया की सबसे तेज गति से उभरने वाली अर्थव्यवस्था भी हैं : मुख्यमंत्री

# मुख्यमंत्री से कैनेडियन हिन्दू चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 04 जनवरी, 2026 को लखनऊ में कैनेडियन हिन्दू चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमण्डल ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधिमण्डल के सभी सदस्यों का स्वागत किया। कैनेडियन हिन्दू चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स के संस्थापक अध्यक्ष श्री नरेश कुमार चावड़ा के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमण्डल ने उत्तर प्रदेश में एम0एस0एम0ई0, धार्मिक पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश की इच्छा व्यक्त की, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।

मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधिमण्डल से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप ट्रेड, टेक्नोलॉजी व टूरिज्म की दिशा में नए प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि 8-9 वर्ष पहले त्योहारों पर बाजार चीन के उत्पादों से भरे रहते थे। हमने वर्ष 2018 में प्रदेश के परम्परागत उद्यमों को 'एक जनपद-एक उत्पाद' योजना के माध्यम से आगे बढ़ाया। इन उत्पादों को डिजाइन, तकनीक व प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया। इन उत्पादों की ब्रांडिंग की गई है। आज प्रदेश के बाजार से चीन के उत्पाद गायब हो गए हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार सितम्बर माह के अंतिम सप्ताह में होने वाले यू0पी0 इंटरनेशनल ट्रेड शो में ओ0डी0ओ0पी0 के उत्पादों को शोकेस का अवसर भी देती है। अब इन उत्पादों को बड़े मंचों पर उपहार स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। सरकार प्रदेश की सभी 96 लाख एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को सपोर्ट कर रही है और इन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारण्टी दे रही है। इनके माध्यम से ढाई करोड़ परिवारों की आजीविका जुड़ी है।

मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधिमण्डल को अवगत कराया कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही, यह दुनिया की सबसे तेज गति से उभरने वाली अर्थव्यवस्था भी है। उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देश के शीर्ष तीन राज्यों में है। यहां देश की सबसे अधिक आबादी निवास करती है। उत्तर प्रदेश में विगत साढ़े आठ वर्षों से किसी प्रकार की अराजकता नहीं है। यहां सुदृढ़ कानून-व्यवस्था है।

मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधिमण्डल को उत्तर प्रदेश की नई गति से परिचित कराते हुए कहा कि यह सम्भावनाओं का प्रदेश है। यहां सुरक्षा, सुव्यवस्था व निवेश की बेहतर स्थिति है। यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। 05 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव फिर से ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार हैं। कैनेडियन हिन्दू चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्य उत्तर प्रदेश में निवेश और तकनीक के साथ एफ0डी0आई0 लाने में मदद कर सकते हैं। एफ0डी0आई0 व फॉर्च्यून-500 कम्पनियों के लिए उत्तर प्रदेश में अलग से पॉलिसी बनाई गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की विरासत से जुड़े स्थलों का प्रतिनिधित्व भी करता है। दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक व आध्यात्मिक आयोजन महाकुम्भ पिछले वर्ष प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में सम्पन्न हुआ। इसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महात्मा बुद्ध व जैन तीर्थंकर परम्परा से जुड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में हैं। इसके दृष्टिगत यहां पर्यटन को विकसित करने में कैनेडियन हिन्दू चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्य बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और लोगों को इन स्थलों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। उन्हें यह भी बता सकते हैं कि सुविधा की दृष्टि से कब-कब इन स्थलों पर जाना चाहिए। प्रदेश के सभी तीर्थ स्थानों तक पहुंचने के लिए एयर तथा रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है।

**प्रतिनिधिमंडल ने उ0प्र0 में एम0एस0एम0ई0, धार्मिक पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश की इच्छा व्यक्त की, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया**

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गत वर्षों में उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है। यहां की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है। देश के एक्सप्रेस-वे का 55 प्रतिशत नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे भी यहां है। प्रदेश में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, सर्वाधिक शहरों में मेट्रो रेल का संचालन, रैपिड रेल व पहला वॉटर-वे भी संचालित हो रहा है। जेवर में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शुभारम्भ शीघ्र ही होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सम्भावनाओं का प्रदेश है। नोएडा में फिल्म सिटी व अपैरल पार्क तथा लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर का नया केंद्र बन रहा है। प्रदेश में 04 डेटा सेंटर संचालित हैं तथा 06 नए डेटा सेंटर संचालित होने जा रहे हैं। उन्होंने लखनऊ में बनने जा रही ए0आई0 सिटी का उल्लेख कर उद्यमियों को यहां की सम्भावनाओं से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधिमंडल को उत्तर प्रदेश में पर्याप्त जल संसाधन व इसकी उर्वरा भूमि से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों के एक्सपोर्ट के लिए कनाडा व अन्य देशों में हम योगदान दे सकते हैं।

कैनेडियन हिन्दू चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स के संस्थापक अध्यक्ष व चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी श्री नरेश कुमार चावड़ा ने मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कनाडा में प्रत्येक वर्ष 'इन्वेस्ट इण्डिया-इन्वेस्ट कनाडा' का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 2026 में यह आयोजन तीन बार किया जाएगा। इसमें से दो आयोजन उत्तर प्रदेश पर केन्द्रित होंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि एम0एस0एम0ई0, धार्मिक पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में उनकी टीम उत्तर प्रदेश में कार्य करेगी। जुलाई-अगस्त व दिसम्बर-जनवरी माह में प्रवासी भारतीयों के कनाडा में जन्में बच्चों को उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराएंगे। साथ ही, उत्तर प्रदेश में 50 बेड का हॉस्पिटल व सीनियर सिटीजन होम्स की स्थापना भी करेंगे।

## मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 04 जनवरी, 2026 को राजभवन, लखनऊ में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से शिष्टाचार भेंट

## मुख्यमंत्री ने 'विकसित भारत-गारण्टी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' अधिनियम-2025 पारित करने के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 06 जनवरी, 2026 को यहां लखनऊ में विकसित भारत-जी राम जी कानून-2025 के सम्बन्ध में आयोजित पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी इन्फ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन के लिए 'विकसित भारत-गारण्टी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' अधिनियम-2025 पारित किया गया है। प्रदेश सरकार इस कानून को पूर्ण संवेदनशीलता, पारदर्शिता तथा प्रभावशीलता के साथ राज्य में लागू कर रोजगार की नयी गारंटी प्रदान करेगी। राज्य सरकार का संकल्प प्रत्येक पात्र को समय पर काम, प्रत्येक गांव में टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण तथा प्रत्येक श्रमिक को सम्मान, सुरक्षा व खुशहाली प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह अधिनियम भारत के ग्रामीण विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। देश के श्रमिकों, किसानों तथा गांवों के विकास के हित में उठाए गए इस कदम का स्वागत व समर्थन किया जाना चाहिए। इस अधिनियम के माध्यम से ग्रामीण भारत प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत@2047 के विजन के अनुरूप राष्ट्र निर्माण में और अधिक सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर सकेगा। उत्तर प्रदेश को विकसित भारत-जी राम जी से अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अस्थायी और अधूरी सम्पत्तियों का दीर्घकालीन लाभ नहीं होता है। वी बी-जी राम जी अधिनियम-2025 रोजगार गारंटी प्रदान करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। यह कार्य विकसित भारत की आधारशिला मजबूत करेगा। विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है, जब राज्य विकसित होंगे। राज्य तब विकसित होंगे, जब हमारी आधारभूत इकाई गांव विकसित होंगे तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, किसान आत्मनिर्भर होगा व श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा व सम्मान मिलेगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस अधिनियम में रोजगार गारण्टी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की गयी है। मानदेय का साप्ताहिक भुगतान होगा। भुगतान में देरी पर मुआवजे की भी व्यवस्था की गयी है। समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अब कानूनी अधिकार बन चुका है। खेती के मौसम में किसानों को मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए राज्यों को बुआई व कटाई के समय

60 दिन तक कार्य विराम का अधिकार प्रदान किया गया है। उस समय वी बी-जी राम जी के कार्य स्थगित रहेंगे। इसके माध्यम से किसान और मजदूर दोनों के हित सुरक्षित रहेंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ग्राम पंचायतें इस अधिनियम के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की चार श्रेणियां निर्धारित कर सकेंगी। अधिनियम के तहत जल संरक्षण की स्थायी व्यवस्था के लिएमें मान्यता प्रदान की गयी है। इनमें बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो टैगिंग, रियल टाइम मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग, ए0आई0 से निगरानी तथा डिजिटल भुगतान जैसी युक्तियां सम्मिलित हैं। अब हाजिरी भरने की औपचारिकताएं नहीं होंगी, बल्कि बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। सेटेलाइट इमेजनरी के माध्यम से स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण की निगरानी की जाएगी। डिजिटल भुगतान के माध्यम से श्रमिकों के खाते में मानदेय की धनराशि भेजी जाएगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस अधिनियम में कैग के मानकों के अनुरूप प्रत्येक 06 माह में अनिवार्य सोशल ऑडिट, डिजिटल एवं बहुस्तरीय समयबद्ध शिकायत निवारण तथा जिला लोकपाल की व्यवस्था सम्मिलित है। यह अधिनियम वित्तीय अनुशासन के साथ-साथ संघीय संतुलन को बनाए रखने में बेहतर योगदान देगा। इसमें केन्द्र व राज्य की साझेदारी 60:40 कार्य मांग आधारित रहेगा। राज्यों को अधिक वित्तीय भागीदारी, स्वामित्व व गुणवत्ता सुधार का अधिकार दिया गया है। राज्यों को अब इस अधिनियम के माध्यम से 17,000 करोड़ रुपये अधिक धनराशि प्राप्त हो सकती है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन राज्यों में श्रमिक वर्ग अधिक है, उन राज्यों को इस अधिनियम के अन्तर्गत ज्यादा कार्य मिलेगा। श्रमिकों का अधिकार बढ़ेगा और भुगतान सुरक्षित होगा। किसान को समय पर श्रम उपलब्ध होगा। अब रोजगार केवल राहत का माध्यम नहीं है, अपितु विकास और आत्मनिर्भरता का भी आधार बनेगा।

**मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 05जनवरी, 2026 को राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 'पद्म विभूषण' स्व. कल्याण सिंह 'बाबूजी' की जयंती के अवसर पर लखनऊ में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।**

**मुख्यमंत्री जी ने कहा कि श्रद्धेय 'बाबूजी' का कार्यकाल सुशासन, विकास और राष्ट्रवादी मिशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सदैव स्मरण किया जाएगा।उन्होंने अपने नाम को उत्तर प्रदेश के 'कल्याण' से जोड़कर निरंतर सार्थक किया।**

**मुख्यमंत्री जी ने 'पद्म विभूषण' स्व. कल्याण सिंह 'बाबूजी' की पावन स्मृतियों को नमन किया।**

# सभी विभाग आवंटित बजट का समय से प्रयोग करें ताकि योजनाएं समय से पूर्ण हो सकें और प्रदेशवासियों को इसका लाभ मिले : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 02 जनवरी, 2026 को यहाँ लखनऊ में वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासन द्वारा विभिन्न विभागों को जारी बजट के व्यय के विषय में वित्त विभाग की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री जी ने बैठक में सभी प्रमुख विभागों के उच्चाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी विभाग आवंटित बजट का समय से प्रयोग करें, ताकि परियोजनाएं और योजनाएं समय से पूर्ण हो सकें तथा प्रदेशवासी इन योजनाओं लाभ उठा सकें। बजट को समय से खर्च करने के लिए अधिकारी निर्णय लेने का सामर्थ्य विकसित करें। जिन विभागों में बजट व्यय की प्रगति धीमी है सम्बन्ध में मुख्य सचिव भी इनीशिएटिव लें। उन्होंने कहा कि जिन विभागों के बजट व्यय की प्रगति धीमी है, उनको चिन्हित करते हुए विभागीय मंत्रियों को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से पत्र जारी किया जाए। उनमें इस कार्य में तेजी लाने के लिए विभागीय मंत्री और अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर प्रत्येक माह बैठक करें। बजट को समय से खर्च करने के लिए प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त न की जाए। योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सभी विभागों के अधिकारी त्वरित निर्णय लें। निर्णय लेने में देरी करने से बजट समय से व्यय नहीं हो पाता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन विभागों को विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से बजट जारी किया जाता है, सम्बन्धित विभाग के मंत्री, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव दिल्ली जाकर केन्द्र सरकार इसके साथ ही, केन्द्र सरकार को पत्र लिखें और फोन से फॉलोअप करते रहें। इस

मुख्यमंत्री जी ने वित्त विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन विभागों के आवंटित बजट के कुछ अंश को किन्ही कारणों से अभी तक जारी नहीं किया गया है, उन विभागों को तत्काल बजट आवंटित किया जाए। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर सभी विभागों के साथ बैठक कर अभी से बजट मांग की समीक्षा करें। आगामी बजट को विभागों को आवंटित करने से पहले उनके पिछले पांच वर्षों के खर्च की समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग नई कार्ययोजना को लेकर अभी से तैयारी शुरू करे। आगामी बजट आवंटन को लेकर केन्द्र सरकार से बेहतर समन्वय बनाएं, ताकि समय से बजट मिल सके।

# राजस्व के सभी मामलों का निपटारा मेरिट के आधार पर तय हो : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 02 जनवरी, 2026 को यहाँ लखनऊ में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य में राजस्व के सभी मामले, चाहे वह पैमाइश, नामांतरण या फिर आबादी दर्ज करने से सम्बन्धित हो, सभी का निपटारा मेरिट के आधार पर तय होना चाहिए। राजस्व विभाग सभी लंबित मामलों में जवाबदेही तय करते हुए उनका निर्धारित समयावधि में निस्तारण सुनिश्चित करे। उन्होंने सभी जनपदों में रोवर आधारित पैमाइश प्रणाली को लागू करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये कि नामांतरण व वरासत के मामलों में ऐसी प्रणाली विकसित की जाए, जिससे यह कार्य ऑटो मोड पर हो सकें। यह नागरिकों को सुगम और समयबद्ध न्याय दिलाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने चकबंदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, नक्शा और रोवर आधारित पैमाइश प्रणाली को लागू करने के प्रयासों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। सभी जिलों में रोवर से पैमाइश के लिए रोवर की खरीद ही नहीं, बल्कि ट्रेनिंग कराने तथा प्रक्रिया को धरातल पर उतारने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। जनपदों में रोवर आधारित पैमाइश को पूर्ण करने के लिए ट्रेनिंग हेतु इंजीनियरिंग कॉलेज,पॉलिटेक्निक एवं आई0टी0आई0 का सहयोग भी लिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री जी ने राजस्व विभाग को निर्देश दिये कि सभी कार्यों की प्रगति में तेजी लाते हुए उन्हें शत-प्रतिशत पूर्ण करने पर फोकस करें। भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण कार्य में तेजी लाते हुए इन्हें शीघ्र पूर्ण किया जाए। विभागीय निगरानी सरल हो और इसका लाभ आमजन को मिले। धारा-80 के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाया जाए। जन समस्याओं के निस्तारण के लिए राजस्व परिषद के स्तर पर कॉल सेण्टर जैसी प्रणाली विकसित की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने चकबंदी प्रक्रिया में तकनीकी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसान रजिस्ट्री, पैमाइश और खसरा पड़ताल से जुड़े सभी लम्बित प्रकरणों का समाधान तय समय-सीमा में अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र जैसी शासकीय सेवाओं को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए रैन बसेरों में व्यवस्थाओं का सुचारु प्रबंधन, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था तथा कम्बल वितरण के सम्बन्ध में राजस्व विभाग को कार्यप्रणाली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों को मिशन मोड में युद्धस्तर पर पूरा किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने ग्राम पंचायतों में स्थापित बाबा साहब डॉ0 भीमराव आंबेडकर की मूर्तियों/स्मारकों को सुरक्षित करने के लिए समाज कल्याण विभाग के सहयोग से बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने लेखपालों को पंचायत सचिवालय में अपना कार्यालय बनाकर जनसमस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर एकीकृत बहुमंजिले कार्यालय का निर्माण हो, जहाँ जिलाधिकारी के साथ-साथ समस्त जनपदीय कार्यालय उसमें समाहित हों।

नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से 05जनवरी, 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिष्टाचार भेंट की।

05 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिष्टाचार भेंट की।

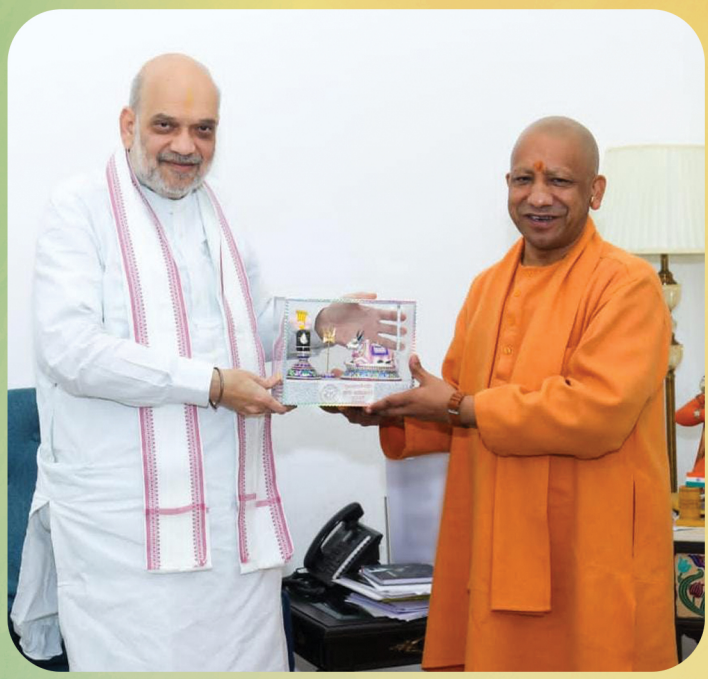

नई दिल्ली में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से 05 जनवरी, 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिष्टाचार भेंट की।

# मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 06 जनवरी, 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

## व्यावसायिक एवं औद्योगिक सम्पत्तियों के पारिवारिक दान विलेखों पर भी स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने व्यावसायिक एवं औद्योगिक सम्पत्तियों के पारिवारिक दान विलेखों पर भी स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। ज्ञातव्य है कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0- 18/2023/995/94-स्टा0नि0-2-2023-700 (29)/2021 दिनांक 03.08.2023 के माध्यम से अचल सम्पत्ति का दान यदि परिवार के सदस्यों के पक्ष में किया जाता है, तो उन पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करते हुए अधिकतम स्टाम्प शुल्क 05 हजार रुपये लिये जाने की व्यवस्था प्रभावी है। यह छूट केवल कृष्य एवं आवासीय संपत्तियों के प्रभावी है।

## उ0प्र0 वैश्विक क्षमता केन्द्र नीति-2024 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली-2025 अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केन्द्र नीति-2024 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली-2025 को अनुमोदित किया है। यह नियमावली उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केन्द्र नीति-2024 के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगी तथा राज्य सरकार द्वारा इसमें संशोधन अथवा समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। इन्वेस्ट यू0पी0 इस नियमावली की नोडल एजेंसी होगी।

## जनपद कुशीनगर की तहसील कप्तानगंज में उपनिबंधक कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने जनपद कुशीनगर की तहसील कप्तानगंज में उपनिबंधक कार्यालय भवन के निर्माण हेतु ग्राम बसहिया उर्फ कप्तानगंज स्थित गाटा संख्या-3308 मी/2.023 हे0 की रिक्त भूमि जो राजस्व अभिलेख में तहसील कप्तानगंज कार्यालय के नाम दर्ज है, में से 0.0920 हे0 भूमि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को कतिपय शर्तों के साथ निःशुल्क आवंटित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इन शर्तों के अनुसार भूमि का हस्तांतरण बिना मूल्य लिये किया जाएगा। इन मामलों में भूमि के बाजार मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

## उपनिबंधक कार्यालय सदर व अभिलेखागार, जनपद झाँसी के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने जनपद झाँसी की तहसील सदर में उपनिबंधक कार्यालय भवन एवं अभिलेखागार भवन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। जनसामान्य को बेहतर सुविधा प्रदान किये जाने के दृष्टिगत उपनिबंधक कार्यालय सदर व अभिलेखागार, जनपद झाँसी का निर्माण कराया जाना है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए निदेशक श्री विशाल सिंह, आईएएस द्वारा प्रकाशित